

AARSI

A Peer Reviewed Multidisciplinary
Annual Journal



Published by
**SLU Arts and H. & P. Thakore
Commerce College for Women**
An Endeavour of
Gujarat Stree Kelavani Mandal



Theme

**National Education Policy 2020 –
Achievements, Challenges & Future Directions**

**Vol. 4
Issue. 4
Year
2026**



ISSN – 2231 : 2897



GSKM - SLU Campus, Ahmedabad.

AARSI - A peer reviewed multidisciplinary annual journal

Issued Date: 15 th June, 2026	Vol. 04	Issue. 04	ISSN: 2331-2897
--	---------	-----------	-----------------

INDEX

Sr. No.	Paper No.	Paper Title	Authors Name	Page No.
1	W01	AI in Teaching, Learning and Research	Dr. Alpesh R. Prajapati	01-05
2	W02 & W03	From Policy to Practice: A Multidimensional Analysis of Implementation Challenges in India's National Education Policy 2020	Dr. Deepa C. Chandwani Dr. Pragnesh B. Dalwadi	06-11
3	W04	Role of NEP-2020 in Transforming Higher Education in India	Dr. Hardik Mehta	12-16
4	W06	NEP 2020: A Transformative Stage Toward Equity and Inclusion in Education	Dr. Manish M. Chudasama	17-22
5	W07 & W16	NEP 2020 and Its Implementation: Examining Challenges in the Indian Education Sector	Dr. Gargi P Patel Dr. Nirali Ketan Shah	23-28
6	W09	National Education Policy to Transform the Education System of 21st Century: Prospects and its Implementation	Dr. Shilpa Jayantilal Patel	29-34
7	W11	Assessing NEP-2020 Implementation in Higher Education: A Comparative Study of Faculty and Student Perspectives	Dr. Vrundani K. Patel	35-43
8	W14	Reimagining Education: A Sociological Analysis of NEP 2020's Challenges and Future Outcomes	Mr. Jitendra Dhebariya	44-50
9	W20	Bridging The Digital Divide in Higher Education: Opportunities and Challenges of Technology Integration under National Education Policy 2020	Dr. Avani Lalitkumar Saraiya	51-58
10	W24	Digital Education under the National Education Policy (NEP) 2020: Challenges and Opportunities for Indian Higher Education	Dr. Jigarkumar Joshi	59-64
11	W25& W26	Digital Education and Technology Integration under NEP 2020	Dr. Ketan J Mehta Dr. Ravjibhai Kotval	65-69
12	W27	Teacher Capacity Building: Evaluating the Effectiveness of AI-Powered NotebookLM in Classroom Pedagogy	Dr. Krishna M. Lakhani	70-74
13	W28	Digital Education and Technology Integration in Higher Education: Students' Perspectives in the Context of NEP 2020	Dr. Rohan Shah	75-81
14	W29	Digital India and Educational Transformation: A Comprehensive Statistical Analysis using Multiple Regression Approach	Dr. Sanjay G Raval	82-87
15	W30& W31	Transforming India's Workforce: A Critical Study of Skill Development Initiatives under the NEP 2020	Dr. Vishal Gupta Dr. Ghanshyambhai M. Anjara	88-94

16	W32	Implementation of National Education Policy 2020 in Higher Education: Opportunities and Constraints	Mr. Bhaveshkumar R. Rathod	95-100
17	W35& P72	Digital Accounting Practices in MSMEs: An Empirical Study of Awareness and Usage Behaviour	Ms. Shivangi N. Patel Dr. Amina Nakhuda	101-104
18	W37	Integrating Indian Knowledge Systems (IKS) in Higher Education: Revitalizing Cultural Roots and Enhancing Learning Outcomes	Dr. Ajitha Shambhu Nair	105-111
19	W40	Indian Knowledge System in New Education Policy	Dr. Rupalben Ashokkumar	112-115
20	W41& W42	Towards Holistic Learning: The Vision of NEP 2020 (An Empirical Analytical Study Based on Primary Data)	Dr. Shital Rathod Dr. Kandarp Chavda	116-120
21	W43	Integrating Ayurveda into Leadership: A Dosha-Centred Approach	Dr. Megha Bhatt	121-128
22	W44	Educating the Inner Self for a Young Nation: Leveraging the Bhagavad Gita and Indian Philosophy to Realize India's Demographic Dividend	Dr. Shweta Zala	129-135
23	W45 & P26	Physical Activity and Sports as Pedagogical Tools in School Education: A Critical Analysis of NEP 2020	Dr. Mukeshkumar B. Baraiya Dr. Yogendra J. Chauhan	136-141
24	W48	Comparative Evaluation of Traditional and Modern Teaching Approaches in Secondary Schools of Ahmedabad City	Dr. Navita Sharma	142-147
25	W49	Portuguese Colonial Legacy and Its Impact on Tourism Development in Diu	Mr. Hardik R. Rathod	148-152
26	W52	English as a Bridge to Higher Education: Women's Academic Inclusion in Post-NEP 2020 India — A Qualitative Secondary-Data Review	Dr. Payal Trivedi	153-156
27	W56& W57	Inclusivity under NEP 2020: A Critical Study of Adivasi (Bhil) Representation in Higher Education	Ms. Saba Syed Dr. Sagar Vyas	157-160
28	W58& W59 P71	Comparative Risk–Return Evaluation of Selected Investment Instruments in the Indian Financial Market	Dr. Khagesh Joshi Ms. Lekshmi Ezhava Dr. Vaibhav Gallani	161-169
29	W60 & 61	Performance Evaluation of Selected Public Sector Banks in India.	Ms. Heenaben Parmar Dr. Ronak Rana	170-177
30	W23	Technology-Driven Higher Education: Insights from Students and Educators	Dr. Janki Mahesh Kotecha	178-181
31	W33	Need And Issues of Digital Education	Dr. Hasmukh Ramanlal Panchal	182-188

NEP-2020 के अंतर्गत भारत में डिजिटल शिक्षा की आवश्यकता और मुद्दे**Need and Issues of Digital Education in India under NEP-2020**

Dr. Hasmukh Panchal
Gujarat Vidyapith, Ahmedabad

Abstract - कोविड-19 ने शक्तिशाली मानव सभ्यता की कई कमजोरियों को उजागर किया है। इसी प्रक्रियामें शिक्षा प्रणाली में, शिक्षा प्रणाली की कई कमजोरियां भी उजागर हुईं, क्योंकि महामारी के कारण इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। जिसकी वजह से लगभग 10 में से 9 बच्चें रेगुलर पढ़ाई के बिना रह गए, जिसका उनके भविष्य के साथ-साथ भारत के भविष्य पर भी बहुत बुरा असर हुआ। यहीं पर हमें डिजिटल शिक्षा की अहमियत को समझना चाहिए, जो महामारी के समय में भारत की शिक्षा पद्धति की एकमात्र रक्षक थी और भविष्य में भारत की शिक्षा पद्धति की रीढ़ बन सकती हैं। NEP-2020 यह सलाह देता है कि प्रत्येक शिक्षा संस्था विषयवस्तु का एक डिजिटल भंडार बनाए जिसमें कोर्सवर्क और गतिविधि आधार सीखने की सामग्री शामिल हो। 2030 तक, NEP-2020 सबको साथ लेकर चलने वाले और बराबरी वाली शिक्षा पद्धति को बेहतर बना देगा। इस पोलिसी में आगे यह भी सुझाव दिया गया है कि एक ओटोनोमस बोडी, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम (NFTF) बनाई जाए, जो स्कूल और हायर एजुकेशन दोनों के लिए लर्निंग, एसेसमेंट, प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर विचारों के फ्री एक्सचेंज के लिए एक प्लेटफॉर्म दे। इसमें कोई शक नहीं कि एजुकेशन का डिजिटलाइजेशन बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं, फिर भी इसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, यह बात इस शोध पत्र में है।

Keywords: – डिजिटलाइजेशन, NEP-2020, ई-लर्निंग, डिजिटल डिवाइड, मुद्दे, ओनलाइन

1. प्रस्तावना – डिजिटल शिक्षा का विचार नया नहीं है। कई सालों से अलग-अलग रूपों में मौजूद है। लेकिन कोविड-19 के बाद फेस-टू-फेस लर्निंग में रूकावट आने के बाद, इसका महत्व बढ़ गया। डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना, डिजिटल सर्विस डिलीवरी और डिजिटल लिटरेसी “डिजिटल इंडिया” पहल के तीन मुख्य स्तंभ हैं। ओनलाइन लर्निंग और टीचिंग एलिमेंट्स के इस्तेमाल से, संस्थान न सिर्फ अपनी प्रक्रिया, किन्तु अपनी शैक्षिक प्रस्ताव को भी डिजिटली बदलने के लिए कदम उठाए हैं। ई-लर्निंग कुछ समय से है, लेकिन NEP-2020 इसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के लिए जरूरी बनाता है। टैबलेट, स्मार्टबोर्ड और वर्चुअल लैब्स जैसे नए प्रौद्योगिकी-सहायक लर्निंग टूल्स के आने से स्कूलों और हायर एजुकेशन संस्थानों में शिक्षा पद्धति बदल गयी है। ओनलाइन शिक्षा NEP-2020 की एक खास प्रायोरिटी है। भारत में डिजिटल लर्निंग के फायदों को ज्यादा करने के लिए NITs और IGNOU जैसी यूनिवर्सिटी और संस्थागत परियोजना चलायेंगे। ट्रेनिंग मटीरियल, क्लासरूम रिसोर्स, एसेसमेंट टूल, प्रोफाइल और DIKSHA और SWAYAM (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) जैसे दूसरे ओनलाइन टूल और प्लेटफॉर्म को नई जानकारी के साथ बदला जाएगा ताकि आसानी से बातचीत हो सके। डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फोर नोलेज शेयरिंग (DIKSHA) प्लेटफॉर्म डिजिटल टेक्सबुक, NCERT से ई-कंटेंट, प्रश्न बैंक वगैरह डाउनलोड करने का एक्सेस देता है। NEP-2020 में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की भी सिफारिश की गई है, जो छात्र के बीच क्रेडिट ट्रांसफर करने में मदद करता है। यह पोलिसी हायर एजुकेशन में कई एंटी और एंजिट ओप्शन देती है, जिसमें छात्र एक साल बाद सर्टिफिकेट के साथ, दो साल बाद डिप्लोमा के साथ और तीन साल बाद बैचलर डिग्री के साथ एंजिट कर सकते हैं।

यूनाइटेड नेशन्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल IV(SDG 4) साफ तौर पर इस बात पर जोर देता है कि शिक्षा पद्धतिका मुख्य मकसद “क्वालिटी एजुकेशन” देना होना चाहिए और इसने 2030 तक सभी देशों को “सबको साथ लेकर चलने वाली और बराबर क्वालिटी एजुकेशन पक्का करने और सभी के लिए ज़िंदगी भर सीखने के मौके बढ़ाने” के लिए उठाए जाने वाले खास कदमों की पूरी समझ दी है। ग्लोबल एजेंडा SDG 4 का ध्यान क्षेत्र, नस्ल, धर्म, रंग, जाति वगैरह की परवाह किए बिना, अच्छी और ज़िंदगी भर चलने वाली शिक्षा को पक्का करके जीवन के स्टैंडर्ड और क्वालिटी को बेहतर बनाना है। इसी के हिसाब से, भारत में ग्लोबल टारगेट पाने पर जोर दिया जा रहा है और इससे भी जरूरी बात यह है कि यह सरकार के शिक्षा पद्धति को पूरी तरह बदलने के लक्ष्यों को पूरा करने की जरूरत की वजह से है। (राजबीर सिंह, 2023, 499)

उद्देश्य – 1. NEP-2020 के अंतर्गत भारत में डिजिटल शिक्षा की आवश्यकता ।
2. NEP-2020 के अंतर्गत भारत में डिजिटल शिक्षा के मुद्दे ।

2. संशोधन पद्धति – वर्णनात्मक पद्धति द्वारा यह शोध कार्य किए है। इस कार्य में रिपोर्ट, शोधपत्र, किताबें, डिजिटल जर्नल के शोध आलेख जैसे सेकन्डरी माहिती का उपयोग किये है। अध्ययन के प्रथम क्षेत्र में विषय वस्तु, दुसरे में संशोधन पद्धति, तिसरे में विश्लेषण-अर्थघटन और चोथे में निष्कर्ष निरूपण किये है।

3. NEP-2020 के अंतर्गत भारत में डिजिटल शिक्षा की आवश्यकता और मुद्दे –

डिजिटल शिक्षा असल में पूरी दुनिया में शिक्षा का भविष्य हैं और यही बात भारत पर भी लागू होती है। यह एक क्रांतिकारी पहल हैं जो लाखों लोग, खासकर स्कूल जाने वाले छात्र को ज्ञान पाने और अपने लिए एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद करेंगी। डिजिटल शिक्षा टेक्नोलोजी के बड़े और विशाल भविष्य को देखते हुए, भारत सरकार डिजिटल शिक्षा को बहुत तेजी से बढ़ावा दे रही है और यह पक्का करने की कोशिश कर रही है कि यह पूरे देश में हर जगह उपलब्ध हो। भारत सरकार का डिजिटल इंडिया कंफेन भी डिजिटल शिक्षा को फैलाने में अहम भूमिका निभा रहा है।

3.1 भारत का शिक्षा मंत्रालय से डिजिटल शिक्षा के लिए पहल-

- 1) ई-पाठशाला – नवंबर 2015 में लोन्च हुआ। ई-पाठशाला NCERT का एक वेब पोर्टल है जो Android Windows और IOS प्लेटफॉर्म के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप के जरिए छात्र, अभिभावक, टीचर्स, एजुकेटर्स और रिसर्चर्स के लिए एजुकेशन रिसोर्स होस्ट करता है। ई-पाठशाला, शिक्षा मंत्रालय और NCERT की एक मिली-जुली पहल है। इसका मकसद शिक्षा के सभी ई-रिसोर्स, जिसमें टेक्सबुक, विडियो, ओडियो और दुसरे कई डिजिटल रिसोर्स शामिल है, जिसे फैलाना और दिखाना है। ई-पाठशाला को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 को पाने के मकसद से भी डिज़ाइन किया गया है, जो सभी के लिए क्वालिटी, सबको साथ लेकर चलने वाली और बराबर की शिक्षा और जिंदगी भर सीखना है और डिजिटल डिवाइड को कम करना है। ई-पाठशाला सीखने के लिए जूम, सेलेक्टिंग, नेविगेटिंग और डिजिटल नोट्स बनाने जैसे इंटरैक्टिव फीचर्स को सपोर्ट करता है।
- 2) DIKSHA का पूरा नाम डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फोर नोलेज शेयरिंग है। यह देश में स्कूली शिक्षा में क्रांति लाने के लिए एक नेशनल प्लेटफॉर्म हैं। DIKSHA, शिक्षा मंत्रालय के तहत NCERT की एक पहल है जिसे 2017 में आरंभ किया गया था। DIKSHA 36 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है और इसे पूरे भारत में टीचर और सीखने वाले, कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। DIKSHA Android ऐप एक शानदार लर्निंग अनुभव देता है, जिससे टीचर और छात्र किताब पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके टेक्सबुक का कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं।
- 3) SWAYAM भारत सरकार का एक प्रोग्राम है। जिसे एजुकेशन पोलिसी के तीन मुख्य सिद्धांतों- क्वालिटी, एक्सेस और इक्विटी को पाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य सभी को सर्वोत्तम शिक्षा और सिखने के संसाधन प्रदान करना हैं, जिसमें सबसे अधिक समाज के वंचित वर्ग को शामिल करना है।
- 4) 2017 में शुरू हुआ SWAYAM PRABHA, 32 DTH चैनलों का एक ग्रुप है जो 24/7 हाई-क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम टेलीकास्ट करता है। यह प्लैटफॉर्म रोजाना कम से कम 4 घंटे के लिए नया कंटेंट होस्ट करता है, जिसे फिर दिन में पाँच बार रिपीट किया जाता है। सामग्री मुख्य रूप से आईआईटी, यूजीसी सहित शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती है। इग्नू, एनआईओएस, एनसीआईआरटी और एनपीटीईएल। स्वयं प्रभा मोबाइल ऐप इनफ्लिबनेट द्वारा विकसित किया गया है जिसका उपयोग सभी कार्यक्रमों मोबाइल फोन पर देखा जा सकता है।
- 5) PM e-Vidya की घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत भारत की टॉप 100 यूनिवर्सिटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगी। पीएम ई-विद्या छात्रों के बीच ऑनलाइन शिक्षण, शिक्षा सामग्री और टीचर की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रोग्राम के तहत, विज्ञान और अंक-शास्त्र के छात्रों के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी के साथ-साथ ई-लैब और ई-प्रयोगशालाए भी बनाई जाएंगी।

3.2 ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा: प्रौद्योगिकी के न्यायसंगत उपयोग को सुनिश्चित करना- (NEP-2020, Page-59)

3.2.1. नई परिस्थितियों और वास्तविकताओं के लिए नई पहलों की ज़रूरत होती है। हाल ही में महामारियों और वैश्विक महामारियों में हुई बढ़ोतरी से यह ज़रूरी हो गया है कि जब भी और जहाँ भी शिक्षा के पारंपरिक और आमने-सामने वाले तरीके संभव न हों, हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक तरीकों के साथ तैयार रहें। इस संबंध में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 टेक्नोलॉजी के संभावित जोखिमों और खतरों को स्वीकार करते हुए, उसके फायदों का लाभ उठाने के महत्व को पहचानती है। यह सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किए गए और उचित पैमाने पर किए

गए पायलट अध्ययनों का आह्वान करती है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि ऑनलाइन/डिजिटल शिक्षा के फायदों का लाभ कैसे उठाया जा सकता है, साथ ही इसके नुकसानों को कैसे दूर या कम किया जा सकता है। इस बीच, सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए, मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म और चल रही ICT-आधारित शैक्षिक पहलों को बेहतर बनाया जाना चाहिए और उनका विस्तार किया जाना चाहिए।

3.2.2. ऑनलाइन/डिजिटल शिक्षा के फायदों का लाभ तब तक नहीं उठाया जा सकता, जब तक कि डिजिटल विभाजन को डिजिटल इंडिया अभियान जैसी ठोस पहलों और किफायती कंप्यूटिंग उपकरणों की उपलब्धता के माध्यम से समाप्त नहीं कर दिया जाता। यह महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग समानता संबंधी चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित करे।

3.2.3. प्रभावी ऑनलाइन शिक्षक बनने के लिए शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण और विकास की आवश्यकता होती है। यह नहीं माना जा सकता कि पारंपरिक कक्षा में एक अच्छा शिक्षक अपने आप ही ऑनलाइन कक्षा में भी एक अच्छा शिक्षक होगा। शिक्षा-पद्धति में आवश्यक बदलावों के अलावा, ऑनलाइन मूल्यांकन के लिए भी एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने पर ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने में कई चुनौतियाँ हैं, जिनमें ऑनलाइन वातावरण में पूछे जा सकने वाले प्रश्नों के प्रकारों पर सीमाएँ, नेटवर्क और बिजली की रुकावटों को संभालना और अनैतिक प्रथाओं को रोकना शामिल है। कुछ प्रकार के पाठ्यक्रम/विषय, जैसे कि प्रदर्शन-कला और विज्ञान के प्रैक्टिकल, ऑनलाइन/डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सीमाओं के साथ आते हैं, जिन्हें नवीन उपायों से कुछ हद तक दूर किया जा सकता है। इसके अलावा, जब तक ऑनलाइन शिक्षा को अनुभव-आधारित और गतिविधि-आधारित सीखने के साथ नहीं जोड़ा जाता, तब तक यह एक स्क्रीन-आधारित शिक्षा बनने की ओर अग्रसर होगी, जिसमें सीखने के सामाजिक, भावनात्मक और मनो-प्रेरक आयामों पर सीमित ध्यान दिया जाएगा।

3.2.4. डिजिटल टेक्नोलॉजी के उभरने और स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक, सभी स्तरों पर पढ़ाई-लिखाई के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बढ़ती अहमियत को देखते हुए, यह पॉलिसी नीचे दिए गए खास कदमों की सिफारिश करती है।(NEP-2020, Page-60)

(a) ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट स्टडी- NETF, CIET, NIOS, IGNOU, IITs, NITs जैसी सही एजेंसियों की पहचान की जाएगी, ताकि वे एक साथ कई पायलट स्टडी कर सकें। इन स्टडी का मकसद यह पता लगाना होगा कि शिक्षा को ऑनलाइन शिक्षा के साथ जोड़ने के क्या फायदे हैं, साथ ही इसके नुकसानों को कम करना होगा। इसके अलावा, इन स्टडी में छात्र-छात्राओं में डिवाइस की लत, ई-कंटेंट के सबसे पसंदीदा फॉर्मेट जैसे जुड़े हुए दूसरे विषयों का भी अध्ययन किया जाएगा। इन पायलट स्टडी के नतीजों को सार्वजनिक तौर पर बताया जाएगा और लगातार सुधार के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा।

(b) डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर- शिक्षा के क्षेत्र में एक खुला, आपस में जुड़ने वाला, लगातार बेहतर होने वाला सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में निवेश करने की ज़रूरत है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कई प्लेटफॉर्म और अलग-अलग समाधानों द्वारा किया जा सकेगा, ताकि भारत के बड़े पैमाने, विविधता, जटिलता और डिवाइस की पहुँच जैसी चुनौतियों को हल किया जा सके। इससे यह पक्का होगा कि टेक्नोलॉजी पर आधारित समाधान, टेक्नोलॉजी में तेज़ी से हो रहे बदलावों के साथ पुराने न पड़ जाएँ।

(c) ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म और टूल- SWAYAM और DIKSHA जैसे मौजूदा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा, ताकि शिक्षकों को शिक्षार्थियों की प्रगति पर नज़र रखने के लिए व्यवस्थित, इस्तेमाल में आसान और कई तरह के सहायक टूल मिल सकें। ऑनलाइन क्लास लेने के लिए दो-तरफ़ा वीडियो और दो-तरफ़ा ऑडियो इंटरफ़ेस जैसे टूल की सचमुच बहुत ज़रूरत है, जैसा कि मौजूदा महामारी ने दिखाया है।

(d) कंटेंट बनाना, डिजिटल रिपॉजिटरी और उसका प्रसार- एक डिजिटल कंटेंट रिपॉजिटरी बनाई जाएगी, जिसमें कोर्सवर्क, सीखने वाले गेम और सिमुलेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी शामिल होंगे। इसमें एक साफ़ सार्वजनिक व्यवस्था भी होगी, जिसके तहत उपयोगकर्ता कंटेंट की असरदारता और गुणवत्ता के आधार पर उसे रेटिंग दे सकेंगे। मज़ेदार तरीके से सीखने के लिए, छात्र-छात्राओं के हिसाब से सही टूल (जैसे ऐप) और भारतीय कला और संस्कृति पर आधारित गेम (gamification) भी कई भाषाओं में बनाए जाएँगे, जिनके इस्तेमाल के निर्देश भी साफ़ तौर पर दिए गए होंगे। छात्र-छात्राओं तक ई-कंटेंट पहुँचाने के लिए एक भरोसेमंद बैकअप व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(e) डिजिटल खाई को पाटना- इस तथ्य को देखते हुए कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसकी डिजिटल पहुँच अभी भी बहुत सीमित है, मौजूदा जनसंचार माध्यमों, जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो और सामुदायिक रेडियो का उपयोग प्रसारण और टेलीकास्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाएगा। छात्रों की अलग-अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम 24/7 अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध कराए

जाएँगे। सभी भारतीय भाषाओं में सामग्री (कंटेंट) पर विशेष जोर दिया जाएगा और यह जरूरी भी होगा; डिजिटल सामग्री को शिक्षकों और छात्रों तक जहाँ तक हो सके, उनकी अपनी शिक्षा के माध्यम में पहुँचाना होगा।

(f) वर्चुअल लैब्स- मौजूदा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे DIKSHA, SWAYAM और SWAYAMPRAKHA का भी वर्चुअल लैब्स बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा, ताकि सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण व्यावहारिक और प्रयोग-आधारित सीखने के अनुभवों तक समान पहुँच मिल सके। SEDG (सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह) के छात्रों और शिक्षकों को उपयुक्त डिजिटल उपकरणों, जैसे कि पहले से लोड की गई सामग्री वाले टैबलेट के माध्यम से पर्याप्त पहुँच प्रदान करने की संभावना पर विचार किया जाएगा और उसे विकसित किया जाएगा।

(g) शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन- शिक्षकों को शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षण-पद्धति में और ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म तथा उपकरणों का उपयोग करके स्वयं उच्च-गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री निर्माता कैसे बनें, इस पर गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। सामग्री के साथ और एक-दूसरे के साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने में शिक्षक की भूमिका पर जोर दिया जाएगा।

(h) ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षाएँ- उपयुक्त निकाय, जैसे कि प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र या PARAKH, स्कूल बोर्ड, NTA और



टेक्नोलॉजी से सशक्त हर शिक्षार्थी, सशक्त भारत की ओर

अन्य: पहचाने गए निकाय मूल्यांकन ढाँचे तैयार करेंगे और उन्हें लागू करेंगे; इन ढाँचों में दक्षताओं का डिजाइन, पोर्टफोलियो, रुब्रिक्स, मानकीकृत मूल्यांकन और मूल्यांकन विश्लेषण शामिल होंगे। शिक्षा प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके मूल्यांकन के नए तरीकों का परीक्षण करने के लिए अध्ययन किए जाएँगे, जिनमें 21वीं सदी के कौशलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

स्रोत – चेट जिपिटी के जरीए यह ईमेज निर्माण की है। दिनांक – 19/05/2026

(i) सीखने के मिश्रित मॉडल: डिजिटल सीखने और शिक्षा को बढ़ावा देते हुए, आमने-सामने (face-to-face) व्यक्तिगत रूप से सीखने के महत्व को पूरी तरह से मान्यता दी गई है। तदनुसार, अलग-अलग विषयों के लिए उपयुक्त रूप से दोहराए जाने हेतु मिश्रित सीखने के विभिन्न प्रभावी मॉडलों की पहचान की जाएगी।

(j) मानक तय करना: जैसे-जैसे ऑनलाइन/डिजिटल शिक्षा पर रिसर्च सामने आएगी, NETF और अन्य संबंधित संस्थाएँ ऑनलाइन/डिजिटल शिक्षण-अधिगम के लिए सामग्री, टेक्नोलॉजी और शिक्षण-पद्धति के मानक तय करेंगी। ये मानक राज्यों, बोर्डों, स्कूलों और स्कूल परिसरों, उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) आदि द्वारा ई-लर्निंग के लिए दिशानिर्देश बनाने में मदद करेंगे।

3.2.5 विश्व-स्तरीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षिक डिजिटल सामग्री और क्षमता निर्माण के लिए एक समर्पित इकाई बनाना (NEP-2020, Page-60) - शिक्षा में टेक्नोलॉजी एक यात्रा है, मंजिल नहीं और नीतिगत उद्देश्यों को लागू करने के लिए विभिन्न इकोसिस्टम के खिलाड़ियों

को एक साथ लाने के लिए क्षमता की ज़रूरत होगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सामग्री और क्षमता निर्माण को एक साथ लाने के उद्देश्य से मंत्रालय में एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी, जो स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों की ई-शिक्षा संबंधी ज़रूरतों का ध्यान रखेगी। चूंकि टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, और उच्च गुणवत्ता वाली ई-लर्निंग देने के लिए विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है, इसलिए एक जीवंत इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि ऐसे समाधान बनाए जा सकें जो न केवल भारत की विशालता, विविधता और समानता की चुनौतियों को हल करें, बल्कि टेक्नोलॉजी में हो रहे तेजी से बदलावों के साथ-साथ खुद भी विकसित होते रहें—ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी 'हाफ-लाइफ' (उपयोगिता की अवधि) हर गुजरते साल के साथ कम होती जा रही है। इसलिए, इस केंद्र में प्रशासन, शिक्षा, शैक्षिक टेक्नोलॉजी, डिजिटल शिक्षण-पद्धति और मूल्यांकन, ई-गवर्नेंस आदि क्षेत्रों से चुने गए विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा।

3.3. भारत में डिजिटल शिक्षा के फायदे – भारत में डिजिटल शिक्षा को शिक्षा का भविष्य माना जा रहा है।

3.3.1. व्यापक पहुंच – इंटरनेट, सेटेलाइट और डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए दूर-दराज के इलाकों तक डिजिटल शिक्षा पहुंचाई जा सकती है। आज भारत में डिजिटल शिक्षा की जो पहुंच है, वह पहले कभी नहीं हो सकती थी, आने वाले सालों के लिए भी पारंपारिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा।

3.3.2. इन्टरैक्टिव और व्यक्तिगत सीखने का अनुभव – डिजिटल एजुकेशन सीखने वालों को एक बिल्कुल नया इन्टरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियन्स देती है। आज हम ब्लैकबोर्ड बेस्ट लर्निंग से बहुत आगे निकल गए हैं और अब इमर्सिव वीडियो और एनिमेशन की अवधारणाएँ के आधार पर बनाया गया, जिससे सीखना दिलचस्प गतिविधि बन गयी है। व्यक्तिगत शिक्षा प्रत्येक छात्र के लिए वन और वन डाउट क्लियरिंग सेशन देता है, इसलिए यह हर किसी की खास ज़रूरतों को पूरा करता है और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ने में मदद करता है।

3.3.3. पाठ्यक्रमों की विस्तृत विविधता – पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में विभिन्न कारणों से सीमित पाठ्यक्रम उपलब्ध थे। भारत में डिजिटल शिक्षा पद्धति में अब ऐसा नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति अपने स्कूल के छात्रों के लिए अलग-अलग विषयों के कोर्से और स्टडी मटीरियल आसानी से, उसकी उँगुलियाँ से पा सकता है। इससे छात्र को अपनी पसंद का कोई भी कोर्स चुनने की आज़ादी मिलती है और वे अपनी पसंद के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं।

3.3.4. लचीला – पारंपरिक शिक्षा की तुलना में डिजिटल शिक्षा का सबसे बड़ा फायदा इनकी लचीलापन है। कोई भी अपनी आवश्यकता के अनुसार SWAYAM PRABHA जैसे डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अध्ययन कर सकता है। सुविधा होगी और पढ़ाई के साथ-साथ दूसरे काम भी मैनेज कर सकेंगे।

3.3.5. प्रभावी लागत – भारत में डिजिटल शिक्षा ने शिक्षा देने के तरीके में क्रांति ला दी है। वो दिन गए जब सिर्फ अमीर और खास लोगों को ही अच्छी शिक्षा मिलती थी। डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार की ज्यादातर पहलें पूरी तरह से मुफ्त हैं।

3.4.1. डिजिटल विभाजन

- ग्रामीण भारत (68%) में इंटरनेट, टेक्नोलॉजी और गैजेट्स की पहुंच बहुत सीमित है।
- बड़ी आबादी टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं है और गैजेट्स तक पहुंच नहीं है।
- कई क्षेत्रों में अभी भी रेगुलर हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है।
- बहरी-ग्रामीण और अमीर-गरीब के बीच डिजिटल डिवाइड, डिजिटल शिक्षा की सबसे बड़ी बाधा है।

3.4.2. भाषा बाधा

- भारत में 22 शेड्यूल भाषाएँ और कई बोलीयों हैं।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज्यादातर कंटेंट हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध है।
- स्थानीय भाषा में कंटेंट की आवश्यकता की प्रक्रिया प्रभावित होती है।

भारत में डिजिटल शिक्षा की चुनौतियाँ और आगे का रास्ता

→ चुनौतियों को समझें, समाधान की दिशा में बढ़ें →

गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और सुलभ डिजिटल शिक्षा हर भारतीय के लिए समावेशी | समानता | सशक्तिकरण

चुनौतियों से अवसरों की ओर

3.4.3. प्रशिक्षण और संचार की कमी

- ज्यादातर टीचर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं।
- ट्रेनिंग की कमी से क्लास में डिस्कशन आती है, छात्रों की रिस्पॉन्सिविटी है और अनुभव बेरंग होता है।
- डिजिटल शिक्षा के लिए ज्यादा स्क्रीन टाइम की आवश्यकता – ऑफ़ो पर स्ट्रेच, निरवर्त, गलत पोस्चर से गर्दन और पोंठ में दर्द।

3.4.4. विशेष आवश्यकता वाले बच्चे

- स्पेशल ज़रूरतों वाले बच्चों को खास ध्यान और देखभाल की ज़रूरत है।
- टीचर्स को इडियम साइन लैंग्वेज और दूसरे मॉड्युल्स में ट्रेनिंग की आवश्यकता है।
- उपयुक्त टूल, संसाधन और समावेशी कंटेंट की कमी एक बड़ी चुनौती है।

डिजिटल शिक्षा का लक्ष्य

डिजिटल पहुंच बढ़ाना

इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार, किफायती डिवाइस और स्थानीय सर पर डिजिटल संसाधन उपलब्ध करना।

स्थानीय भाषा में कंटेंट

सभी भारतीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण कंटेंट तैयार करना और अनुवाद को बढ़ावा देना।

टीचर्स की ट्रेनिंग

डिजिटल टूल, रेगुलरी और संगठित कौशल पर नियमित प्रशिक्षण और सपोर्ट देना।

समावेशी शिक्षा

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त टूल, संसाधन और सहायक वातावरण सुनिश्चित करना।

स्क्रीन टाइम संतुलन

उचित स्क्रीन टाइम, हेल्थ केम और एरगोनॉमिक्स पर जागरूकता बढ़ाना।

प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन

विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म को आम में जोड़ना और बेहतर समन्वय स्थापित करना।

किफायती और सुलभ

डिजिटल शिक्षा को किफायती बनाना और इसे हर वर्ग तक पहुंचाना।

आत्मनिर्भर और सशक्त समाज

चुनौतियों को अवसर में बदलें, डिजिटल शिक्षा से उज्जवल भारत गढ़ें।

3.4. भारत में डिजिटल शिक्षा की चुनौतियाँ – भारत में डिजिटल शिक्षा की कई चुनौतियाँ हैं।

3.4.1. डिजिटल विभाजन – जब भी डिजिटल एजुकेशन के बारे में सोचते हैं तो कुछ बुनियादी बातें दिमाग में आती हैं, जैसे- इंटरनेट, टेक्नोलॉजी और गैजेट्स। ये बेजिक चीजें ज्यादातर ग्रामीण भारतीयों को नहीं मिलती, जहां भारत की आबादी का 68 प्रतिशत है। ज्यादातर लोग टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं हैं और उनके पास गैजेट्स तक पहुंच नहीं है। देश का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां अभी भी रेगुलर हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं पहुंची है। ये सभी शहरी और ग्रामीण एवं अमीर और गरीब भारत में मौजूद डिजिटल डिवाइड को बनाते हैं, जो भारत में डिजिटल एजुकेशन के लिए सबसे बड़ी रुकावट है।

3.4.2. भाषा बाधा – भारत एक ऐसा देश है जहाँ भाषाई विविधता बहुत ज्यादा है। 22 शेड्यूल्ड भाषाएँ हैं और कई दूसरी बोलीयाँ भी हैं। यह एक बड़ी चुनौती है क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद ज्यादातर कंटेंट या तो हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में है।

3.4.4. प्रशिक्षण और संचार की कमी – डिजिटल शिक्षा का पता लगाने के लिए टेक्नोलॉजी के अनुसार ट्रेनिंग लेनी होगी। ज्यादातर टीचर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं हैं और इसलिए उन्हें क्लास लेते समय लगातार दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इससे छात्रों की रिडम भी बिगड़ती है और पूरा एक्सपीरियंस बोरिंग हो जाता है। डिजिटल शिक्षा के लिए ज्यादा स्क्रीन टाइम की आवश्यकता होती है, जिसमें आँखों पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। इसके अलावा, सिरदर्द और गलत पोस्चर जैसी दूसरी दिक्कतें भी हैं, जिससे गर्दन और पीठ में दर्द होता है।

3.4.3. विशेष आवश्यकता वाले बच्चे – स्पेशल जरूरतों वाले बच्चों को पढ़ाई में खास तरह का ध्यान और देखभाल की जरूरत होती है। इसके अलावा, टीचर्स को इंडियन्स साइन लैंग्वेज और दूसरे मॉड्यूल्स में भी ट्रेनिंग देने की जरूरत है। आज डिजिटल शिक्षा को सभी चुनौतियों और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की बहुत आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी में तेजी से तरक्की हो रही है, इसलिए लगातार बदलते डिजिटल एजुकेशन इकोसिस्टम की जरूरत है। भारत में डिजिटल शिक्षा का मुख्य फोकस केवल सीखने के पहलू पर होना चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट दूसरे एरिया है, जिन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। टीचर्स और छात्रों को डिजिटल एजुकेशन के बारे में बेसिक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। टेक्नोलॉजी को इस तरह से बनाया गया है कि इसकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल हो सके। भारत में डिजिटल शिक्षा को किरायाती बनाना, इसे आम लोगों तक पहुँचाने का एक और जरूरी पहलू है। अलग-अलग डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ना और उनमें तालमेल बिठाना भी बहुत फायदेमंद होगा। **स्रोत –** चेट जिपिटी के जरीए यह ईमेज निर्माण की है।

4. निष्कर्ष – NEP-2020 के अंतर्गत डिजिटल शिक्षा से देश के पूरे शिक्षा सेक्टर में क्रांति लाने और भारत को एक नोलेज इकॉनमी में बदलने की क्षमता है। आज जरूरत है कि बुनियादी बातों पर ध्यान दिया जाए और लगातार बदलती डिजिटल एजुकेशन टेक्नोलॉजी और बेहतर इंटरनेट, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ आसानी से मिलने वाले और सस्ते गैजेट्स के साथ अपडेट रहा जाए। जिससे भारत को युनिवर्सल एजुकेशन पाने के सही रास्ते पर रखा जा सके। आज भारत की एजुकेशन वर्ल्ड क्लास बन गई है। अब कई विदेशी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन भी भारत में आकर अपनी ब्रांच खोल रहे हैं। इनमें से कई इंस्टिट्यूशन ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। फिर भी भारत में ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के सामने कई चैलेंज हैं। इसमें अभी भी बहुत तरक्की करनी है।

संदर्भ –

1. Dalal Rajbir Singh, Jul.-Aug., 2023, Digitalization of Education under NEP, 2020: Prospects and Challenges, International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM) Volume 3, Issue 4, pp: 498-504, www.ijhssm.org
2. National Education policy, 2020, Ministry of Human Resource Management, Government of India.
3. Meena Satya Narayan, March 2024, Online and Digital Education in Contemporary India, International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT) Volume 4, Issue 2, pp: 47-50.
4. Budhia Netramani and Behera Sasmita, 2023, Challenges and Opportunities of Digital Education in India, Asian Journal of Education and Social Studies Volume 45, Issue 3, Page 1-7, Article no.AJESS.100746 ISSN: 2581-6268
5. A.Mary Diana, August 2020, A Study on Impact of Digital Education in India. Dogo Rangsang Research Journal ISSN : 2347-7180 UGC Care Group I Journal Vol-10 Issue-08 No. 02.
6. <https://www.ndear.gov.in/> Date – 10-04-2026
7. <https://www.ndear.gov.in/diksha-infrastructure.html> Date – 10-04-2026

About SLU College

Shree Lalshankar Umiyashankar Arts and Harivadan & Padmaben Thakore Commerce College for Women, which was established in 1920 as an endeavour of Gujarat Stree Kelvani Mandal, has the proud privilege of being the first women's college in Ahmedabad. The college is recognised under Section 2 (f) and 12 (b) of UGC Act 17th June, 1972. The college runs various programmes in affiliation with Gujarat University such as - B.A., B.Com., and M.Com. The BS-BBA programme was added from the academic year 2025-2026. The college also runs several add-on programmes like Fashion Design and Computer Courses at the ICTC centre located at the SLU Campus.

Editorial Advisory Board

Dr. Chandrika Raval (Secretary, GSKM)
Dr. Himmat Bhalodiya (Principal, SLU College)
Dr. Sirali Mehta
Dr. Preeti Oza

Editors – in Chief

Dr. Madhusudan Mukerjee
Dr. Kandarp Chavda

Editorial Team

Dr. Rashmi Soni	Dr. Shailaja Dhruva
Dr. Shital Rathod	Dr. Mukeshkumar Baraiya

College Website

www.slucollege.org

Aarsi Email Id

sluaarsi@gmail.com